International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

एशिया -प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों के सन्दर्भ में क्वाड देशों की वैविध्यपूर्ण भूमिका

नारायणी शुक्ला

शोध छात्रा,राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,प्रयागराज -211002,उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

21वीं सदी में एशिया- प्रशांत क्षेत्र की भू-राजनीतिक महाशक्तियों या उभरती शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जहां अनेक संभावनाएं हैं, वहीं यह क्षेत्र चुनौतियों से रहित नहीं है। इस क्षेत्र में अनेक परंपरागत एवं गैर-परंपरागत चुनौतियां विद्यमान है। अतः इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन स्थापित कर साझी समृद्धि हेतु साझी प्राथमिकताओं की पहचान कर सामान्य मूल्यों और समानहित अथवा स्वहित से संचालित देशों के मध्य अनेक सुरक्षा समुदायों का निर्माण होता है जिनमें 'क्वॉड' प्रमुख है। क्वाड देश चार प्रमुख लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक अंतर सरकारी संगठन है जो इस क्षेत्र में शांति एवं सहयोग स्थापित कर साझी समृद्धि स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहें है। चीन,जो कि एशिया- प्रशांत क्षेत्र में अपनी आक्रामक विस्तारवादी नीतियों के जरिए वर्चस्व स्थापित करने का जो प्रयास कर रहा है उनका सामना करने के लिए क्वाड एवं क्वाड के पूरक संगठन ऑकस और स्क्वाड की भूमिका महत्वपूर्ण है जो सामूहिक रणनीति अपना कर इस क्षेत्र में शक्ति -संतुलन स्थापित करने तथा समस्याओं के समाधान में योगदान कर रहे हैं। इस शोध पत्र में एशिया प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाओं की दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर क्वॉड देशों के मध्य विविध मंचों के माध्यम से हो रहे सहयोग का शोधार्थी द्वारा अवलोकनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

विशिष्ट शब्द-एशिया -प्रशांत, हिन्द -प्रशांत, भूराजनीति, भू अर्थ, समृद्धि की क्षमता, सामरिक प्रतिद्वंदिता, सहकारी रणनीति, समन्वय तंत्र, साझी प्राथमिकता, सयुंक्त प्रयास, विस्तारवादी नीति, क्वाड, ऑकस, स्क्वाड, PGII, CTPP, RCEP, IPEF।

शोध प्रविधि: -अंतर-अनुशासनात्मक प्रकृति के इस शोध के लिए ऐतिहासिक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। जिसमें प्राथमिक व द्वितीय स्रोतों का प्रयोग सम्मिलित है।

प्रस्तावना-

21वीं सदी एशिया की सदी है।अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्धारण में एशिया -प्रशांत क्षेत्र की भू- राजनीति का महत्वपूर्ण स्थान है। यह क्षेत्र समृद्धि की क्षमता से परिपूर्ण एवं सामरिक प्रतिद्वंद्विता की संभावनाओं तथा चुनौतियों से भरा हुआ है।शीतयुद्धोत्तर विश्व व्यवस्था में भू -अर्थ का महत्व काफी अहम है ।इस संदर्भ में अवसर और संभावनाओं को परखते हुए भौगोलिक एकीकरण कर हित धारकों द्वारा नए-नए शब्द गढ़े गए इसी संदर्भ में "एशिया -प्रशांत" और "हिंद -प्रशांत" जैसे शब्द अस्तित्व में आए।

एशिया -प्रशांत क्षेत्र में भू- राजनीति के संदर्भ में लोकतांत्रिक देश के मध्य सहयोग बढ़ाने में 'क्वाड 'संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह एक अनौपचारिक अंतर सरकारी संगठन है जिसके संगठन करता स्वयं चार लोकतांत्रिक देश अमेरिका (दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र),भारत (दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र), जापान एवं ऑस्ट्रेलिया हैं। उनके बीच समुद्री सहयोग 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के मानवी संकट का जवाब देने के लिए एक समन्वय तंत्र के रूप में शुरू हुआ ।लेकिन वर्तमान में सभी लोकतंत्र और जीवंत अर्थव्यवस्थाएं एक व्यापक एजेंडे पर काम करती हैं ।जिसमें सुरक्षा,आर्थिक और स्वास्थ्य मुद्दों से निपटना शामिल है। समय के साथ-साथ क्वाड की कूटनीति में उतार-चढ़ाव आया है। यह एक अनौपचारिक गठबंधन के बजाय एक लचीला समूह है जहां एक तरफ जापान ने शुरू में सदस्य देशों की लोकतांत्रिक पहचान पर जोर दिया,वहीं

भारत कार्यात्मक सहयोग पर बल देने में अधिक सहजता व्यक्त की ।ऑस्ट्रेलियाई नेता यह धारणा बनाने में अनिच्छुक रहे कि यह समूह एक अनौपचारिक गठबंधन है।इस चौकड़ी सुरक्षा समूह का प्रमुख उद्देश्य चीन द्वारा पेश की जाने वाली दीर्घकालिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना है। वास्तविक चुनौतियों के संदर्भ में देखें तो क्वाड के लिए अनौपचारिक भू -राजनीतिक एवं भू -आर्थिक अवश्यकता है क्योंकि यह चार विभिन्न सदस्यों को चीन के मुकाबले समान स्थिति बनाए रखते हुए सुरक्षा गतिविधियों का समन्वय करने के लिए एक व्यवहारिक प्रारूप प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में इसके सदस्य देश भारत,जापान, आस्ट्रेलिया में अमरीका ने अपने द्वीपक्षीय, त्रिपक्षीय और चतुर्भुज रक्षा और सुरक्षा संबंधों को उत्तरोत्तर मजबूत किया है।

क्वाड सदस्यों सहित एशिया- प्रशांत क्षेत्र के अन्य लोकतांत्रिक देशों, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, बांग्लादेश,श्रीलंका के मध्य साझी प्राथमिकताओं पर सहकारी रणनीति अपनाकर कार्य करना चीन के आक्रामक नीतियों का शांतिपूर्ण प्रतिकारी पहल करना संभव है। लोकतांत्रिक देशों के मध्य सहयोग एशिया- प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने एवं क्षेत्र की शांति,स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। एशिया -प्रशांत क्षेत्र की शांति विश्व की शांति के लिए महत्वपूर्ण है।

एशिया में लोकतंत्र के लिए चुनौती कठिन है। वर्तमान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दृश्य जो कई दशकों से एशिया में चला आ रहा है लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच प्रतियोगिता की कैसे एशिया को शासित किया जाये ।सोवियत संघ के विघटन के उपरांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति में लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं मूल्यों के प्रति आम सहमति बनती दिखाई दी।समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति के रूप में उभर कर आया।अतः यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोकतांत्रिक देशों के मध्य सहयोग के साझा दृष्टिकोण एवं साझी प्राथमिकताएं क्या है? इस क्षेत्र की सामूहिक सुरक्षा चुनौतियां क्या है?

एशिया -प्रशांत क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ –

एशिया -प्रशांत की चुनौतियों में परंपरागत एवं गैर परंपरागत चुनौतियां विद्यमान है। चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीतियां, राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय अस्थिरता, प्राकृतिक आपदा,आतंकवाद (साइबर,नार्को आतंकवाद),बढ़ता सैन्यकरण,अनियमित वाहन, सूचना एवं संचार,मानव तस्करी,अशिक्षा, गरीबी,समावेशी विकास की समस्या प्रमुख है। अतः लोकतांत्रिक देशों द्वारा सहकारिता को अंजाम देकर एशिया -प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा,सहयोग, समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सकता है जो मानव कल्याण की सच्ची सेवा होगी।

एशिया- प्रशांत क्षेत्र अत्यधिक आपदा प्रवण क्षेत्र है। सुनामी,भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात जैसी विश्व की कुल आपदाओं में से तीन चौथाई इसी क्षेत्र में घटित होती है। यह क्षेत्र अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है जैसे उच्च तापमान,वर्षा में असामान्य उतार -चढ़ाव आदि । इस क्षेत्र में लघु द्वीपीय देश और विकासशील तटवर्ती देश (littoral Country)शामिल हैं । इसके कारण यह सुभेद्यताएँ इस क्षेत्र को अधिक गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं । अतः इस क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित सहयोग के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं -तापमान,वर्षा में असामान्य उतार -चढ़ाव आदि।इस क्षेत्र में लघु द्वीपीय देश और विकासशील तटवर्ती देश (littoral Country)शामिल हैं । इसके कारण यह सुभेद्यतायएँ इस क्षेत्र को अधिक गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं।अतः इस क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित सहयोग के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं –

- पूर्व चेतावनी प्रणाली
- आपातकालीन तैयारी
- आपदा संवेदनशीलता आदि।

हाल ही में,क्वाड देशों ने (HADR) **समझौते पर हस्ताक्षर किया है।**

क्वाड का उदय-

एशिया -प्रशांत क्षेत्र भारत- जापान संबंधों की धुरी है ।भारत जापान के साथ मिलकर शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। दोनों देश लोकतांत्रिक, आर्थिक दृष्टि से संपन्न सामरिक एवं तकनीकी रूप से मजबूत हैं ।ऐसे में दोनों देशों का उत्तरदायित्व बनता है कि एशिया महाद्वीप में समानता, सहयोग एवं शांति बनी रहे एशिया -प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामुद्रिक सुरक्षा,वैज्ञानिक शोध, सामुद्रिक शिक्षा,मत्स्य प्रबंधन करने

की दिशा में अपार संभावनाएं हैं ।यह सहयोग तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब चीन अपने सैन्य बल तथा "डेट ट्रैप डिप्लोमेसी","चेक बुक डिप्लोमेसी" द्वारा एशिया -प्रशांत क्षेत्र की अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहा हो । लोकतांत्रिक देशों के सामरिक भागीदारी और सहयोग ब्रुनेई, वियतनाम,फिलीपींस जैसे छोटे और द्वीपीय देश को चीन की अराजकता के खिलाफ खड़े होने का बल मिलता है।

क्वाड के सभी सदस्य समूह का समर्थन करने के लिए अपने-अपने तरीके अपनाए भारत और जापान जहां विवादित क्षेत्र पर चीन के साथ भिड़ गए वहीं आस्ट्रेलिया ने अपनी राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पूर्वी एशियाई शक्ति के प्रभाव को तरजीह दी। अमेरिका एशिया -प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से सहमत दिखाई दिया। क्वाड 0.1 के खत्म होने के एक दशक बाद इन चार देशों ने समान लक्षण को आगे बढ़ाने के लिए खुद को फिर से एकजुट होने के लिए तैयार पाया जिसमें एक नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, नेविगेशन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान सम्मिलित है।

क्वाड का उदय रणनीतिक अवधारणा में 'हिंद -प्रशांत, को सदस्य देशों के स्तर पर एवं वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता का संकेत देता है। 2007 में भारतीय संसद के समक्ष तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के" दो समुद्रों का संगम "भाषण से शुरू होकर एशिया -प्रशांत क्षेत्र के गठन के पारंपरिक समझ में बदलाव दिखाई देता है। वर्तमान में देश की प्रमुख शक्तियों की सोंच में परिपक्वता का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। जापान और अमेरिका के लिए सुरक्षा के उनके पारंपरिक समझ पूर्वोत्तर एशिया की संकीर्ण सीमाओं से विस्तारित दिखाई देती है। अमेरिका ने घोषणा की कि उसके हित का क्षेत्र अब "हॉलीवुड से बॉलीवुड" तक फैल गया है ।भारत के लिए, क्वाड में इसकी सदस्यता का महत्व यह है कि यह भारत के रणनीतिक सोंच में विकास का प्रतिनिधित्व करती है जो 1990 के दशक की शुरुआत में इसके 'पूर्व की ओर देखो नीति, के साथ शुरू हुई थी। आस्ट्रेलिया ने भी महसूस किया कि हिंद महासागर उसके राष्ट्रीय हित के लिए महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्वाड सदस्य देश अपने सैन्य गतिविधियां तेज कर दी है। इसका प्रमुख उदाहरण 'मालाबार अभ्यास'है,जो यह दिखाता है कि यह वैश्विक ध्यान से बचनहीं पाया है | साथ ही साथ सयुंक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा समझौतों के रूप में द्विपक्षीय सैन्य संबंध भी बढ़े हैं । समान रूप से महत्वपूर्ण सदस्य देशों के बीच उच्चस्तरीय 2+2 संवाद राजनयिक सारणी की एक नियमित विशेषता बन गई है। 2001 में 'ऑकस'जैसा संगठन अस्तित्व में आया जिसके तीन सदस्यों में 2 क्वाड के सदस्य देश हैं। भारत और जापान इसके सदस्य नहीं है। यह एशिया- प्रशांत क्षेत्र की शांति प्रबंधन में क्वाड का पूरक साबित हो सकता है। एशिया -पैसिफिक की चुनौतियों के संदर्भ में जून,2023 में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने 'स्क्वाड 'नमक समूह की घोषणा की जिसके चार प्रमुख देश संयुक्त राज्य अमेरिका,ऑस्ट्रेलिया,जापान और फिलिपींस सदस्य हैं, जो रणनीतिक सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण है। उप-क्षेत्रीय समस्याओं को हल करने के साथ इस क्षेत्र में क्वाड के उद्देश्यों को विस्तार दे रहे हैं जो चीन के आक्रामक विस्तारवादी नीतियों के प्रतिकारी पहल के रूप में नियमित सुरक्षा व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं।

क्वाड देशों की भूमिका –

समूह के सदस्यों को यह एहसास है कि सुरक्षा निवारण उपाय और राजनीतिक समन्वय उनके उद्देश्य का एक प्रमुख घटक है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। यदि वे क्षेत्र व्यवस्था का आधार बनने वाले मूल्यों की रक्षा के लिए एक प्रभावी गठबंधन बनाना चाहते हैं तो उन्हें क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों के प्रति अधिक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है।

मार्च 2021 में, वर्चुअल क्वाड शिखर सम्मेलन इसी समझ को प्रतिबिंबित किया ।जैसे ही कोविड -19 का संक्रमण दुनिया में बढ़ा,क्वॉड देशों ने 2022 के अंत तक एक बिलियन वैक्सीन खुराक प्रदान करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ क्वाड वैक्सीन साझेदारी को डिजाइन करने के लिए चिकित्सा प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल विनिर्माण और लॉजिस्टिक में अपने अद्वितीय शक्तियों का लाभ उठाया।

बढ़ते हुए जलवायु संकट को देखते हुए एक क्वाड वर्किंग ग्रुप बनाने का संकल्प लिया।आम चुनौतियों से निपटने का यह संयुक्त प्रयास क्वाड के क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता। संयुक्त रूप से नई तकनीकी विकसित करने के लिए क्वाड मोल्ड प्रौद्योगिकियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रहा है। क्वाड देशों द्वारा साझा किए गए मूल्यों की छवि में भविष्य के लिए क्वाड ने आतंकवाद निरोध में सहयोग के अवसर तलाशने की अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीति BRI के विकल्प के रूप में G7की एक पहल द्वारा "वैश्विक अवसंरचना एवं निवेश के लिए

साझेदारी " (PGII) का प्रयास किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकासशील देशों में आवश्यक अवसंरचना के वित्त पोषण के लिए अगले 5 वर्षों में 200 बिलियन डालर जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस पहल का उद्देश्य चीन की 'बेल्ट एंड रोड'पहल को प्रतिसंतुलित करना है। यह G7 पहल चार प्रमुख श्रेणियों में परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रही है -स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रणालियां, लैंगिक समानता तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में I भारत और जापान द्वारा BRI के विकल्प के रूप में "एशिया -अफ्रीका समृद्धि गलियारा " (AAGC)शुरू किया गया। इस द्विपक्षीय साझेदारी का लक्ष्य अफ्रीका में गुणवत्तापूर्ण और सतत (सामाजिक और परिवहन संबंधी) अवसंरचना विकास परियोजनाओं और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। भारत के समक्ष विशेष रूप से उसकी राजनीतिक चिन्ताएँ हैं जो छोटे दक्षिण एशियाई देशों और हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में BRI अवसरचनाओं एवं कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लेकर चिंतित है। भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए "मौसम परियोजना "आरंभ की गई है ।कई उद्देश्यों के साथ "सागर" अर्थात क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। इसके उद्देश्य हैं -

- समुद्री हितों की रक्षा करना
- तटीय क्षेत्रों में आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना
- समुद्री खतरों से निपटने के लिए सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देना
- समुद्री नियमों,मानदंडों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए विश्वास में वृद्धि करना और सम्मान को बढ़ावा देना

पड़ोसी देशों में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए इन देशों की सहायता तथा निवेश और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करना भारत के प्रमुख प्रयास है।

पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बढ़ती आर्थिक समृद्धि और व्यापार में तेजी से वृद्धि के साथ हाल ही में कई महत्वपूर्ण आर्थिक समझौते सामने आए जिनमें ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP),क्षेत्रीय व्यापक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता आर्थिक भागीदारी (RCEP)तथा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) प्रमुख हैं ।इन समझौते का उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर करना और पारस्परिक निवेश को बढ़ावा देना है। उदाहरण के लिए पर्यावरण और श्रम सुरक्षा मानकों में टैरिफ सुविधा और सामंजस्य बनाकर ये व्यापार समझौते क्षेत्र और विश्व स्तर पर चीन और जापान की प्रमुख आर्थिक स्थिति के साथ -साथ संयुक्त राज्य अमरीका और चीन के बीच व्यापार संघर्ष और एक सामंजस्य पूर्ण बाजार की यूरोपीय दृष्टि दोनों से प्रभावित हैं।सीपीटीपीपी एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें वर्तमान में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 11 देश शामिल है। आस्ट्रेलिया ब्रुनेई, कनाडा, चिली,जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम ।अमेरिका TPP के लिए बातचीत से 2017 में बाहर हो गया। मूल TPP में 11 देशों ने बातचीत जारी रखी और CPTPP तैयार किया जिस पर मार्च,2018 में चिली में हस्ताक्षर किया गया और दिसंबर 2018 के अंत में लागू किया गया। 2021 की शुरुआत में U. K. CPTPP में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाला पहला गैर-संस्थापक देश बना।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन 'आसियान'के 10 सदस्य देशों (ब्रुनेई,इंडोनेशिया, कंबोडिया लाओस मलेशिया,म्यांमार,फिलीपींस,सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम) और उनके पांच मुक्त व्यापार देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है।अन्य प्रमुख साझेदार आस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और कोरिया गणराज्य है।इस प्रकार RCEP में वर्तमान में 15 देश शामिल हैं, जिनमें 7 देश CPTPP के समवर्ती सदस्य हैं। RCEP आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और व्यापार और निवेश संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ सदस्य देशों के बीच विकास अंतर को कम करने में मदद करने के लिए मौजूदा आसियान +1 मुक्त व्यापार समझौते पर आधारित है। प्रारंभ में भारत में,भारत ने भी वार्ता में भाग लिया,लेकिन फिर RECP में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया । RCEP भी चीन और जापान के बीच हुए कुछ प्रमुख समझौते में से एक है। RCEP दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है और इसमें दुनिया की GDP का लगभग 30% हिस्सा सम्मिलित है। दुनिया की लगभग 1/3 आबादी RCEP सदस्य देशों में रहती है। यह समझौता सदस्य देशों के लिए एक नई रूपरेखा तय करता है। समझौते के लागू होने के बाद अगले 20 वर्षों में,सदस्यों के बीच व्यापार किए जाने वाले सामानों पर अधिकांश टैरिफ समाप्त होने की योजना है। हालांकि सीमा शुल्क नियमों पर अधिकांश टैरिफ समाप्त होने की योजना है। हालांकि सीमा शुल्क नियमों में कोई सामंजस्य नहीं होगा ।इसके अलावा RCEP का लक्ष्य सदस्यों के बीच निवेश और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ावा देना है ।इस उद्देश्य से निवेशको और निवेशों की सुरक्षा

के लिए समान प्रावधान बनाए जाएंगे। इसके अलावा समझौते में व्यापार विवादों को निपटाने के लिए तंत्र शामिल है। हालांकि, सामान्य तौर पर RCEP समझौते में व्यक्तिगत सदस्यों के लिए बड़ी संख्या में छूट प्रावधान शामिल है और CPTPPकी तुलना में कम मानकों के साथ यह बहुत कम व्यापक है।

IPEF अमेरिका के1 दशक से भी अधिक पुराने ' एशिया के लिए धुरी' कार्यक्रम का हिस्सा है। इसमें अमेरिका सहित एक भौगोलिक निर्माण के रूप में हिंद प्रशांत क्षेत्र की पुनः कल्पना की गई है। (क्वाड भी सामान गतिविधि का हिस्सा है)। वर्ष 2017 में ट्रांस पेसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता(CPTPP/ मूल रूप से TPP) से बाहर निकलने के पश्चात,IPEF अमेरिका को पूर्वी एशिया और आसियान क्षेत्र में आर्थिक नेतृत्व को पुनः प्राप्त करने में सहायक है। IPEF संयुक्त राज्य अमेरिका और एशियाई क्षेत्र के 13 अन्य देशों के बीच एक (प्रस्तावित) समझौता है, जिसमें आस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, दारुस्सलाम, फिजी, भारत,इंडोनेशिया, जापान मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड शामिल है। वियतनाम समझौते पर अभी भी बातचीत चल रही है और इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया। आखिरी दौर की बातचीत जुलाई 2023 में कोरिया के बुसान में हुई थी। यह देखना बाकी है कि समझौते में किस हद तक और कड़े कदम शामिल किए जाएंगे। हालांकि इस बात पर पहले से संदेह है कि क्या समझौता प्रभावी होगा ।क्योंकि इसमें मुक्त व्यापार समझौते की पारंपरिक विशेषताएं,विशेष रूप से टैरिफ सुविधा शामिल नहीं है।

IPEF डिजिटल अर्थव्यवस्था आपूर्ति, श्रृंखला, सुरक्षा और लचीलापन, स्वच्छ ऊर्जा और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों सहित कई कई क्षेत्रों को संबोधित करता है। यह समझौता भाग लेने वाले देशों को उन सभी में भाग लेने के बिना व्यक्तिगत पहल में भी शामिल होने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा संभवत कई एशियाई देशों की संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच चयन करने से बचने और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य करने की इच्छा के कारण है। हालांकि, IPEF वर्तमान में व्यापार संबंधों के लिए पर्याप्त दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य और स्थिरता प्रदान नहीं करता।IPEF अमेरिका के यह दर्शाने के तरीके का एक रूप है कि यूरोप में युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित करने और आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से रूस का उग्र रूप से मुकबला करने के बावजूद, अमेरिका अपनी इस दृष्टिकोण को नहीं भूला है की एशिया और चीन की चुनौती अमेरिका के एजेंडे में प्रमुख स्थान रखता है।

क्वाड में सचिवालय या स्थायी निर्णय लेने वाली संस्था का अभाव है ।जिसके बिना समूह के लिए जलवायु संकट का सामना करना मुश्किल होगा। अब तक यह केवल संयुक्त सैन्य अभ्यास करने, संयुक्त मोर्चा और कूटनीति सामंजस्य प्रदर्शित करने करने के लिए एक साथ आया है ।इसलिए क्वाड के लिए वैश्विक समुदाय को आश्वस्त करना और जलवायु संकट से निपटने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए एक समेकित और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है। यहाँ तक कि चीन जैसे इंडोपेसिफिक में क्वाड की बढ़त को रोकने के लिए समूह के पुनरुद्धार के पीछे प्रेरक शक्ति माना जाता है ने 2060 तक कार्बन नेट- शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं की घोषणा की है। क्वाड सयुंक्त अनुसंधान करने, लोगों और न्याय को अपनी जलवायु एजेंडे के मूल में रखने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं। अमेरिका और भारत के उभरते कदम क्वाड,इंडो पैसिफिक और दुनिया भर में उचित परिवर्तन दृष्टिकोण को संस्थागत बनाने के लिए एक उपयुक्त आधार के रूप में काम कर सकते हैं। जलवायु एजेंडे से संबंधित दृष्टिकोण और कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए क्वाड लोकतंत्र के सार का लाभ उठा सकता है। अब समय आ गया है कि इस सदी के सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक खतरों में से एक से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग का व्यापक, समावेशी और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाये जाने की जरूरत है।

क्वाड ने विकासशील देशों में समूह के बुनियादी ढांचे के निवेश को बेहतर ढंग से प्रसारित करने के लिए एक और इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप के गठन की भी घोषणा की । यह विकास संकेत देता है कि क्वाड ने हाथ-पांव मारने और नैतिक दिखावे को समाप्त करने का संकल्प लिया है जो अब तक चीन की बेल्ट एंड रोड पहल की प्रतिक्रिया की विशेषता रही है। इस संबंध में तंत्र की स्थापना करके और इसे ब्लू डॉट नेटवर्क जैसी अन्य पहलुओं के साथ जोड़कर, क्वाड ने संकेत दिया है कि वह अंततः चीन की विशाल बुनियादी ढांचा विकास पहलों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक निवेश और सार्वजनिक पूंजी लगाने के लिए तैयार है ।इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य के भविष्य को लेकर लड़ाई कई महीनों से सुर्खियों में बनी हुई है। नये सिद्धांत जारी किए गए कि क्वाड स्टेटमेंट अधिक प्रतिबंधात्मक प्रतिस्पर्धियों को सीधी चुनौती देते हुए एक "खुले,उच्च मानक नवाचार "पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने का वादा करता है। तकनीकि मानकों को तैयार करने के लिए क्षेत्रीय समूहों को एक साथ रखकर क्वाड प्रमुख मानकों को विकसित करने,उन्हें विश्व स्तर पर लागू करने और चीन जैसे अधिक शत्रुतापूर्ण

खिलाड़ियों के मुकाबले एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी लाभ स्थापित करने की उम्मीद करता है , जिनके पास क्वाड- डिजाइन को स्वीकार करने के अलावा बहुत कम विकल्प होंगे। प्रौद्योगिकी वास्तुकला,सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पहल के माध्यम से समूह प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी के लिए आपूर्ति लाइनों को सुरक्षित करने के लिए भी तेजी से आगे बढ़ा है। सेमीकंडक्टर 5G तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को संयुक्त रूप से विकसित करने और संचालित करने के लिए इस तरह की स्पष्ट शक्ति का खेल बनाकर क्वाड ने चीन के सामने चुनौती पेश कर दी है। इरादे के ऐसे स्पष्ट बयान के साथ, वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा का भविष्य संभवतः यहां से गर्म हो जाएगा।

निष्कर्ष-

अतः एशिया -प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा बनाए रखना वैश्विक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शांति का आशय युद्ध के अभाव से ज्यादा व्यापक है ।अतः इस क्षेत्र में बदलते शक्ति समीकरण को देखते हुए लोकतांत्रिक देशों में शक्ति समन्वय कर संयुक्त उद्यम की नीति अपनाकर साझा हितों के उद्देश्य से सहकार को अंजाम देना महत्वपूर्ण आवश्यकता है। चार लोकतांत्रिक देशों का संगठन क्वाड की भूमिका इस क्षेत्र की शांति, सहयोग, विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। बदलते भू- राजनीतिक एवं भू आर्थिक आयाम को देखते हुए इस क्षेत्र में कई छोटे-बड़े सुरक्षा समूह द्विपक्षीय,त्रिपक्षीय संबंध के रूप में उभर रहे हैं। परंतु इस क्षेत्र में सैद्धांतिक एवं भौतिक एवं तकनीकी रूप से सर्वोच्च स्थिति रखने वाले क्वाड सदस्य देश चीन की विस्तारवादी नीतियों के प्रतिकारी संतुलन के लिए तथा अन्य देशों के विकास का समान अवसर व सहयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है। अतः यह क्षेत्र क्वाड के लिए अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न करने के साथ -साथ कई अवसर एवं संभावनाओं के द्वार खोलता है। जो निरंतर बौद्धिक विचार-विमर्श और शोध का विषय है।

सन्दर्भ सूची –

1. Baldwin, A. David. (1993).*Neorealism And Neo liberalism :The Contemporary Debate*. New York, Colambia University Pres.
2. Chinoy, R. Sujan. (2020).*Asia Between Multipolarism And Multipolarity.* New Delhi, KW Publisher Pvt, Ltd.
3. Fukuyama, Francis. (2020).*The End Of History And The Man*. India, Penguin Random House.
4. Gen,Maj. & Sharma, B. K. & Rasheed Adil. (2015*).Indian Ocean Region :Emerging Strategic Coopration, Compition And Conflict Scenarios.* India, VIJ Books Pvt. Ltd.
5. Hundal,Tajendra. (2021).*India And Australia In Indo - Pacific :Dynamics Of Defense, Diplomacy And Diaspora.* India, Notion Press.
6. Mahaptra, Chintamani. (2020).*Rise Of The Indo - Pacific : Perspective, Dimension And Challenges.* New Delhi, Pentagon Press.
7. Menon, Shivshankar. (2021).*India And Asian Geopolitics.* India. Brooking Institution.
8. Mohan, C. Raja. (2012).*Samudra Manthan :Sino Indian Rivalry In The Indo -Pacific*. India, Carnegie Endowment For International Peace.
9. Nye, S. Joseph. (2005).*Soft Power :The Means To success In World Politics*. New York, Public Affairs Publication.
10. Pant, V. Harsh. (2019).*China Ascendant :Its Rise And Implications.* India, Harper Collins.
11. Pant, V. Harsh. (2021).*Politics And Geopoltics Decoding India's Neighborhood Challenge.* India, Rupa Publication.
12. Sakhuja, Vijay & Narula, kapil.. (2016).*Maritime Safety And Security In The Indian Ocean*. India, VIJ Books Pvt. Ltd.

13. Singh, Sudhir. (2014).*India In Emerging Asia.* New Delhi, Pentagon Press.
14. Waston, C. G. (2007).*Qaud A Novel Every A Action Triggers A Reaction*. New Delhi, Razorbill Publication
15. सिन्हा, मनिनी सौम्या. (2019, सितम्बर). *पड़ोस में लोकतंत्र घाटा (डेमोक्रेसी डेफिसिट)*. वर्ल्ड फोकस.13(138),64-67.
16. शरण, श्याम. (2010).*कोविड -19 के भू -राजनीतिक तथा भू -आर्थिक आयाम*. योजना.10:10-12.
17. कुओक, लिन. (2021, जून 8). *एशिया -प्रशांत क्षेत्रीय सुरक्षा का परिचय*. https://www.iiss.org
18. झाँ,पंकज &खान, ए. शमशाद. &मिश्रा, राहुल. (2016, मई 12). *भारत और एशिया - प्रशांत आर्थिक सहयोग -मामले के विकास*. नई दिल्ली, भारतीय वैश्विक परिषद सप्रू हाउस. https://www.icwa.in
19. मिश्रा,विवेक &दास, उदयन. (2019, मई 4*). इंडो -पैसिफिक और क्वाड समूह :भारत की हिन्द प्रशांत नीति कितनी समावेशी, कितनी सफल.* ओआरएफ.https://www.orfonline.org.
20. Narayan, lakshman. (2021,December). *Explained Understanding Me U. S. Strategy Of 'Asia Pivot '*. The Hindu Newspaper.
21. ओट, मार्टिन. (2020,दिसंबर 22). *एशिया में लोकतंत्र*.hettps://www.wilsoncenter.org.
22. मिश्रा, राहुल. (2021, जनवरी 22). *इंडोपैसिफिक में भारत की त्रिकोनीय गठबंधनों की पहल*. डीडब्लू https://www.dw.com.
23. पाटिल, समीर. (2022 अप्रैल 29). *प्रजातंत्र, प्रौद्योगिकी और भू -राजनीति*. ओ आरएफ. hettps://www.orfonline.com.
24. लूथरा, गिरीश. (2022, जनवरी 19). *हिन्द -प्रशांत क्षेत्र :समुद्र से जुड़े मसले और महासागर सम्बंधित प्रशासन व्यवस्था*. ओआरएफhettps://www.orfonline.com.
25. Oren, Indo. (n. d.).Democratic Peace : Kantian Peace, liberal peace. hettps:// www.britanica.com
26. मोहन, सी. राजा.(2022). *अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध : भारत और महामारी के दौर की भू -राजनीति*. ओआरएफ.hettps://www.orfonline.com.
27. Wiendiek, Sebastian & Satrk, Peter. (2023,September 12*).Asia's free Trade Agreements in Focus:CPTPP, RCEP and IPEF*.
28. https://www.roedl.com/insights/asia-free-trade-agreements-cptpp-rcep-ipef
29. Singh, Bhanu Uday (n. d). Anmol Anand Asked : *Why does India focus on ASEAN Centrality in its Indo - Pacific Strategy? What are the Challenges Involved in it*.
30. https://www.idsa.in/askanexpert/india-focus-on-asean-centrality-in-its-indo-pacific-strategy
31. Saha, Pramesha & Mishra, Vivek. (2023,june 8*).Quad 3.O: A security - Oriented Reincarnation?*
32. https://www.orfonline.org/expert-speak/quad-3-0-a-security-oriented-reincarnation/?amp
33. Pant, V. Harsh. & Mattoo Shashank. (2021,September 23). *The Rise and Rise of the 'QUAD' : Setting an Agenda For India*.https://www.orfonline.org/research/the-rise-and-rise-of-the-quad-setting-an-agenda-for-india/?amp
34. Sharma, Mihir Swaroop & Kasliwal, Riya & Mukhopadhyay, Abhijeet. (2021,September 2021).*Resilient, Inclusive, and Free: Towards a Post-Pandemic Indo-Pacific Region*.
35. https://www.orfonline.org/research/resilient-inclusive-and-free/?amp
36. Rajgopalan,Pillai Rajeshwari. (2021,September 23*).Does AUKUS Augment or Diminish the Quad?*.
37. https://www.orfonline.org/research/does-aukus-augment-or-diminish-the-quad/?amp
38. Roy, Aprna. (2021,September 24).*On the climate crisis, a four-point agenda for Quad meeting*
39. https://www.orfonline.org/research/on-the-climate-crisis-a-four-point-agenda-for-quad-meeting/?amp
40. Pant, V. Harsh & Mattoo,Shashank.(2021,September 23*).The Quad Gains Momentum as Strategic Realities Evolve*.

41. https://www.orfonline.org/research/the-quad-gains-momentum-as-strategic-realities-evolve/?amp
42. Rossiter, Ash & Cannon, J. Bredon. (2023,February 23*).Quad in the Indo-Pacific: Role of Informality in Countering China*.
43. https://isdp.eu/publication/quad-in-the-indo-pacific-role-of-informality-in-countering-china/
44. Taylor, Monique. (2023,July *).AUKUS, Advanced Capabilities and Defense Integration in the Indo-Pacific.*
45. https://www.isdp.eu/publication/aukus-advanced-capabilities-and-defense-integration-in-the-indo-pacific/
46. Smith, A. Sheila. (2021,May 27).*The Quad in the Indo-Pacific: What to Know*.https://www.cfr.org/in-brief/quad-indo-pacific-what-know
47. Silversten, Benjamin. (2022,May2020).*The Quad Needs More Than Bilateral Agreements to Achieve Its Space Goals*.
48. https://carnegieendowment.org/2022/05/20/quad-needs-more-than-bilateral-agreements-to-achieve-its-space-goals-pub-87145
49. Bhandari, Konark. (2021,October 21).*India, the Quad, and the Future of Outer Space*.
50. https://carnegieindia.org/2021/10/21/india-quad-and-future-of-outer-space-pub-85610
51. Bhattacharya, Debasis. (2021,November 24).QUAD: *दुनिया की ताकत और भारत की ताकत के लिए*.
52. https://www.orfonline.org/hindi/research/quad-a-force-for-global-good-indias-strategic-imperatives/?amp
53. Rajgopalan, Pillai Rajeshwari. (2023,January 30*).QUADसे परे: हिंद-प्रशांत में तेज़ी से बढ़ता सुरक्षा सहयोग का प्रयास*.
54. https://www.orfonline.org/hindi/research/beyond-quad-booming-security-cooperation-efforts-in-the-indo-pacific/?amp
55. Andreopoulos, Marcus. (2022,September 30).*The Sino-Indian Border: The Front Line of the Quad*.https://thediplomat.com/2022/10/the-sino-indian-border-the-front-line-of-the-quad/
56. *क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की भागीदारी*.2022,May24.
57. https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/35354/Prime_Ministers_participation_in_the_Quad_Leaders_Summit
58. Bazi, Pairman. (2023,April 24*).The Geopolitics of Asia-Pacific: Containment of China*.https://thegeopolitics.com/the-geopolitics-of-asia-pacific-containment-of-china/
59. झाँ, पंकज &खान, ए. शमशाद &मिश्रा, राहुल. (2016, मई 12*).भारतऔर एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग : मामले के विकास*.
60. Uthamaraj Pissonia Asked*: Why APEC is not letting India join as its member?*.
61. https://www.idsa.in/askanexpert/APECisnotlettingIndiajoin
62. Dwivedi, Dr. Akshat. (2024,May, 14).*From QUAD to Squad: Informal Alliances in the Indo-Pacific*.
63. https://www.geopoliticalmonitor.com/from-quad-to-squad-informal-alliances-in-the-indo-pacific/
64. Haldar, Sayantan & Sharma,Abhishek. (2024,May, 24).*Squad and the rise of minilateralism in the Indo-Pacific*.
65. https://www.orfonline.org/expert-speak/squad-and-the-rise-of-minilateralism-in-the-indo-pacific